NEWSLETTER

शनिवार, 24 फ़रवरी 2024 | वॉल्यूम - 86

Interview | Weekly cotton bales market | Weekly cotton arrival | Important News

भारतीय कपड़ा उद्योग ईएलएस कपास पर आयात शुल्क हटाने का स्वागत करता है

GOLD : 62325
SILVER : 70450
CRUDE OIL : 6356

गुजरात के जूनागढ़ जिले के किसानों की मांग

कपास की सटीक जानकारी और किसान आंदोलन का कौनसे राज्य में क्या असर है इसकी संदर्भ में गुजरात के जूनागढ़ जिले के कपास किसान श्री जलपेश भाई से एसएसआई (SIS) टीम ने बातचीत की ।

जलपेश भाई सालो से कपास की खेती करते है। इस साल 22 वीघा में कपास की बुआई की थी। गुजरात में कपास का उत्पादन अच्छा हुआ है। इस साल कपास की क़्वालिटी पिछले साल की तुलना में उनके क्षेत्र में कम अच्छी है।

आगे उन्होंने बताया की गुजरात राज्य में किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के लिए बताय की कोई भी फसल का उत्पादन हो पर सरकार उसके मापदंड तय करके रखती है। उसके अनुसार ही वह किसान से खरीदी करती है, सरकार मापदंड अनुसार अच्छी क़्वालिटी का ही का MSP मूल्य मिल पाता है पर अगर 22 वीगा में कोई भी फसल का उत्पादन करते है तो सारा ही अच्छी क़्वालिटी हो यह संभव नहीं होता, जिससे जो उत्पादन की क़्वालिटी अच्छी नहीं होती है उसको तो किसान को खुल्ले बाजार में MSP से कम मूल्य पर बेचना ही मज़बूरी है। जिसकी वजह से किसान को नुकसान होता है। आगे वह बताते है सरकार जो सीसीआई द्वारा खरीदी करती है उसका केंद्र (CCI Centre) वह हर क्षेत्र में नहीं होता जिसकी वजह से किसान को एक जगह से दूसरी जगह अपने अपने उत्पादित माल को ले जाने का ट्रांपोटेशन का खर्चा होता है जिसकी कोई गिनती नहीं है।

उनके अनुसार उत्पादन की लागत: कपास की खेती में हुए खर्चे से कम हो जाती है। इसमें बीज, खाद, जल, कृषि उपकरण, प्रयोगिता, मजदूरी आदि शामिल होती है। इन खर्चों को पूरा करने के लिए किसानों को अधिक पैसे की आवश्यकता होती है।मौसमी आपातकाल: किसानों को अकाल, बारिश की कमी, बाढ़, बर्फबारी, विपरीत मौसम आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उत्पादन और उपज कम हो सकती है और उन्हें नुकसान हो सकता है।MSP तय करने से पहले इस करने भी विचार करना चाहिए।

कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price - MSP) भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है ताकि किसानों को उत्पादन के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित की जा सके। यह मूल्य बाजार की प्रासंगिकता, मांग और उत्पादन की लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है ताकि किसानों को उत्पादन के लिए उचित मूल्य मिल सके और उन्हें संतुष्टि और सुरक्षा की भावना हो सके।

कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि किसानों की आर्थिक स्थिति, बाजार की प्रतिस्पर्धा, उत्पादन की लागतें, और विभिन्न अन्य प्रासंगिक तत्व। इन सभी कारकों का विवेकपूर्ण विश्लेषण करके सरकार किसानों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को हरित क्रांति योजना (Green Revolution) के तहत निर्धारित किया जाता है। यह मूल्य बाजारी की अनियमितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है ताकि उत्पादन के संभावित बदलावों का समावेश किया जा सके।

कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रति क्विंटल (100 किलोग्राम) में निर्धारित किया जाता है। यह मूल्य क्षेत्रवार और वित्तीय वर्ष के आधार पर बदलता रहता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार के बीच समझौते किए जाते हैं।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास बेचने का अधिकार होता है, लेकिन बाजारी स्थिति के अनुसार वे अपने उत्पादों को बाजार मूल्य पर भी बेच सकते हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उत्पादों को खरीदने की गारंटी दी जाती है। यह किसानों को उत्पादन के लिए उचित प्रोत्साहन प्रदान करता है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

Download Our App "SIS CONNECT" For Daily Updates. CLICK HERE

FOR MORE INFORMATION
CONTACT - +91 - 91119 77775

सीएआई ने 2023-24 कॉटन सीज़न के लिए अपना जनवरी का कॉटन प्रेसिंग अनुमान 294.10 लाख गांठ पर बरकरार रखा है

COTTON ASSOCIATION OF INDIA

INDIAN COTTON BALANCE SHEET FOR THE SEASON 2023-24 AND 2022-23

Estimated as on 31st January 2024

Details	2023-24		2022-23	
	(in lakh b/s)	(in'000 Tons)	(in lakh b/s)	(in'000 Tons)
Supply				
Opening Stock	28.90	491.30	24.00	408.00
Cotton Pressing	294.10	4999.70	318.90	5421.30
Imports	22.00	374.00	12.50	212.50
Total Supply	**345.00**	**5865.00**	**355.40**	**6041.80**
Demand				
Mill Consumption	280.00	4760.00	280.00	4760.00
Consumption by SSI Unit	15.00	255.00	15.00	255.00
Non- Mill Consumption	16.00	272.00	16.00	272.00
Total Domestic Demand	**311.00**	**5287.00**	**311.00**	**5287.00**
Available Surplus	**34.00**	**578.00**	**44.40**	**754.80**
Exports	**14.00**	**238.00**	**15.50**	**263.50**
Closing Stock	**20.00**	**340.00**	**28.90**	**491.30**

कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने 2023-24 सीज़न के लिए कपास की प्रेसिंग संख्या के जनवरी के अनुमान को 294.10 लाख गांठ 170 किलोग्राम पर बरकरार रखा है। जनवरी 2024 के अंत तक कुल कपास आपूर्ति 210.05 लाख गांठ होने का अनुमान है, जिसमें आगमन, आयात और शुरुआती स्टॉक शामिल है। जनवरी 2024 के अंत तक कपास की खपत 110.00 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि 31 जनवरी 2024 तक निर्यात शिपमेंट 9.00 लाख गांठ होने का अनुमान है।

सीएआई ने जनवरी 2024 के अंत में स्टॉक 91.05 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है, जिसमें कपड़ा मिलों के पास 41.00 लाख गांठ और सीसीआई, महाराष्ट्र फेडरेशन और अन्य के पास शेष 50.05 लाख गांठ शामिल है। 2023-24 सीज़न के अंत तक (30 सितंबर, 2024 तक) कुल कपास आपूर्ति 345 लाख गांठ होने का अनुमान है।

सीएआई की फसल समिति ने 20 फरवरी, 2024 को अपनी बैठक में 2023-24 सीज़न के लिए कपास की खपत का अनुमान 311 लाख गांठ बनाए रखा। सीजन के लिए कपास प्रेसिंग का अनुमान 294.10 लाख गांठ है। सीजन के लिए कपास का आयात 22 लाख गांठ और निर्यात 14 लाख गांठ होने का अनुमान है। 30 सितंबर, 2024 तक अंतिम स्टॉक 20 लाख गांठ होने का अनुमान है।

देश भर के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में इस सप्ताह कपास की आवक

SMART INFO SERVICES

ALL INDIA COTTON WEEKLY ARRIVAL

CALL : 91119 77775

STATE	19.02.24	20.02.24	21.02.24	22.02.24	23.02.24	24.02.24
PUNJAB	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,000
HARYANA	3,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500
UPPER RAJASTHAN	5,000	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000
LOWER RAJASTHAN	3,500	3,500	3,500	2,500	3,000	3,000
NORTH ZONE	13,000	11,500	11,500	11,500	11,700	11,500
GUJRAT	38,000	38,000	38,000	38,000	37,000	33,000
MADHYA PRADESH	8,000	7,500	7,500	7,500	7,500	6,000
MAHARASHTRA	40,000	40,000	40,000	35,000	40,000	40,000
CENTRAL ZONE	86,000	85,500	85,500	80,500	84,500	79,000
KARNATAKA	11,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ANDHRA PRADESH	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
TELANGANA	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
TAMILNADU	800	800	800	300	500	500
SOUTH ZONE	23,800	24,800	24,800	24,300	24,500	24,500
ODISHA	1,700	1,300	1,300	1,000	900	800
TOTAL	124,500	123,100	123,100	117,300	121,600	115,800
ARRIVAL IN 170 Kg.						

भारतीय कपड़ा उद्योग ईएलएस कपास पर आयात शुल्क हटाने का स्वागत करता है

भारतीय कपड़ा उद्योग ने न केवल एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास पर आयात शुल्क हटाने के कदम का स्वागत किया है, बल्कि यह भी उम्मीद है कि सरकार को जल्द ही कपास की अन्य किस्मों पर शुल्क खत्म करने की आवश्यकता का एहसास होगा। इस फैसले के बाद, बाजार धारणा पर तत्काल दबाव के कारण गुजरात बाजार में कपास की कीमतें 356 किलोग्राम की प्रति कैंडी 600 रुपये कम हो गईं। हालांकि, बुधवार को कीमतों में कुछ हद तक सुधार आया।

केंद्र सरकार ने ईएलएस कॉटन पर आयात शुल्क हटा दिया है. देश ईएलएस कपास के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। वर्तमान में, सूती धागे की बारीक गिनती के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर लगभग 11 प्रतिशत आयात शुल्क लागू है। टीटी इंडस्ट्री के प्रबंध निदेशक और भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) के पूर्व अध्यक्ष को बताया, "यह एक योग्य कदम है। हमें उम्मीद है कि कपास की अन्य किस्मों पर आयात शुल्क की जल्द या बाद में समीक्षा की जाएगी।

सरकार को उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता और एमएसपी के माध्यम से किसान की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत ईएलएस कपास का शुद्ध आयातक है क्योंकि देश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कपास नहीं उगाता है। आयात शुल्क ने 60/1 और उससे अधिक के .धागे से बने भारतीय मूल्यवर्धित उत्पादों को महंगा बना दिया था। किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ. सरकार ने एक गलती को सुधार लिया है

महाराष्ट्र के इचलकरंजी के पावरलूम मालिक भरत शाह ने बताया, "आयात शुल्क हटाने से हाई-एंड फैब्रिक की कपड़ा मूल्य श्रृंखला में कुछ राहत मिल सकती है। अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े और परिधानों के लिए उत्पादन लागत थोड़ी कम हो सकती है।" उन्होंने कहा कि कॉटन के मार्केट सेंटीमेंट पर कुछ दिनों तक ही मनोवैज्ञानिक असर देखने को मिल सकता है. सरकार के फैसले से कुल मिलाकर बाजार की गतिशीलता नहीं बदलेगी।

दिल्ली के एक प्रमुख सूती धागा व्यापारी ने कहा कि कुल कपास की आवश्यकता में से ईएलएस कपास की खपत बहुत कम है। इसलिए इस फैसले का बहुत सीमित असर होगा. यह गुजरात के शंकर-6 कपास का स्थान नहीं ले सकता क्योंकि ईएलएस कपास बहुत महंगा है। व्यापार सूत्रों ने कहा कि खबर सामने आने के बाद मंगलवार को गुजरात बाजार में कपास की कीमतें 600 रुपये प्रति कैंडी तक कम हो गईं। कपास खरीदारों के इंतजार करो और देखो की नीति के कारण धारणा कमजोर हुई। हालाँकि, बुधवार को कीमतों में ₹200 प्रति कैंडी की बढ़ोतरी हुई।

TOP 4 NEWS OF THE WEEK

- **महाराष्ट्र: बीड जिले छत्रपति संभाजीनगर में कपास खरीद मूल्य को लेकर किसानों का आंदोलन।**
छत्रपति संभाजीनगर: बीड जिले के दो किसानों ने बाजार में कपास की कम कीमतों को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

- **केंद्र ने 5 फसलों - कपास, मक्का, तुअर, उड़द और मसूर के लिए एमएसपी पर 5 साल की गारंटी वाली खरीद का प्रस्ताव रखा है**
हालाँकि, किसानों द्वारा मांगे गए कानून पर कोई प्रतिबद्धता नहीं है जो निजी व्यापारियों को कम से कम बेंचमार्क दर पर खरीदने के लिए मजबूर कर सके, यदि अधिक नहीं ।

- **तेलंगाना ने सीसीआई से कीमतों में गिरावट रोकने के लिए कपास की खरीद जारी रखने का आग्रह किया है**
तेलंगाना के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने भारतीय कपास निगम (सीसीआई) से राज्य में कपास की खरीद जारी रखने का आग्रह किया है ।

- **तेलंगाना: सीसीआई ने 12.31 लाख टन कपास की खरीद की**
राज्य के लगभग सभी कपास उत्पादक जिलों में कपास की तीसरी चुगाई का काम चल रहा है और पहली और दूसरी चुगाई का भारी स्टॉक अभी भी उत्पादकों के पास पड़ा हुआ है।

कॉटन फिजिकल मार्केट फ़रवरी माह के चौथे सप्ताह कॉटन के भाव में तेजी वाला माहौल रहा।

यह सप्ताह कॉटन फिजिकल मार्केट के लिए तेजी वाला रहा। नार्थ ,साउथ और सेंट्रल झोन में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त देखी गई।

नार्थ झोन में पंजाब और हरीयाणा और राजस्थान में क्रमशः 25, 140 और 125 रुपए प्रति मंड की बढ़त देखने को मिली।

वही सेंट्रल झोन के गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में क्रमशः 400 और 200 रूपए की बढ़त दर्ज की गई वहीं महाराष्ट्र में कोई हलचल देखने को नहीं मिली।

साउथ झोन मार्केट में ओडिशा और तेलंगाना में क्रमशः 400 और 300 रूपए प्रति कैंडी की बढ़त देखी गई। जबकि कर्नाटक में कोई हलचल देखने को नहीं मिली।

SMART INFO SERVICES
india.smartinfo@gmail.com
Call : 91119 77775

DATE: 24.02.2024

WEEKLY COTTON BALES MARKET

STATE	STAPLE LENGTH	19.02.24		24.02.24		CHANGE
		LOW	HIGH	LOW	HIGH	
NORTH ZONE						
PUNJAB	28.5	5,625	5,675	5,650	5,700	25
HARYANA	27.5/28	5,575	5,575	5,600	5,715	140
UPPER RAJASTHAN	28	5,075	5,725	5,150	5,850	125
CENTRAL ZONE						
GUJARAT	29	57,500	58,000	58,200	58,400	400
MADHYA PRADESH	29	56,800	57,300	57,200	57,500	200
MAHARASHTRA	29+ vid.	57,000	57,800	57,200	57,800	0
SMART INFO SERVICES CALL : 91119 77775						
SOUTH ZONE						
ODISHA	29.5+	58,500	58,600	58,900	59,000	400
KARNATAKA	29 mm	57,500	58,000	57,700	58,000	0
TELANGANA	29.5/30 mm 78-80 RD	57,500	58,000	57,800	58,300	300

NOTE : There may be some changes in the rate depending on the quality.
Punjab, Haryana and Rajasthan rates in maund the rest in Candy

NEWSLETTER

Saturday, 24 February 2024 | Volume - 86

Interview | Weekly cotton bales market | Weekly cotton arrival | Important News

Indian textile industry welcomes removal of import duty on ELS cotton

GOLD : 62325
SILVER : 70450
CRUDE OIL : 6356

Demand of farmers in Junagadh district of Gujarat

SSI team talked to Mr. Jalpesh Bhai, a cotton farmer from Junagadh district of Gujarat, regarding the accurate information and practical problems about cotton and what is the impact of farmers' movement in this state.

Jalpesh Bhai has been cultivating cotton for years. This year cotton was sown in 22 bighas. Cotton production has been good in Gujarat. This year the quality of cotton is less good in their area as compared to last year.

He further said that there is no effect of farmers movement in Gujarat state. The government sets the criteria for MSP (Minimum Support Price) no matter what crop is produced. According to that, it purchases from the farmer, as per the government criteria, only good quality gets the MSP price, but if any crop is produced in 22 kg, then it is not possible for all the crops to be of good quality, due to which the production is affected. If the quality is not good, the farmer is forced to sell it in the open market at a price lower than the MSP. Due to which the farmer suffers loss. He further explains that the center (CCI Centre) which is procured by the government through CCI is not available in every area, due to which the farmer has to incur the transportation cost of taking his produced goods from one place to another, which cannot be counted Is.

According to him, the cost of production is reduced by the expenses incurred in cotton cultivation. This includes seeds, fertilizers, water, agricultural equipment, utilities, labor etc. To meet these expenses, farmers require more money. Seasonal emergency: Farmers may face problems like famine, lack of rain, flood, snowfall, adverse weather etc., which may reduce production and yield. And they may suffer losses. This should also be considered before deciding the MSP.

The Minimum Support Price (MSP) for cotton is set by the Indian Government to ensure minimum income to the farmers for production. This price is determined on the basis of market relevance, demand and costs of production so that farmers can get a fair price for the produce and give them a sense of satisfaction and security.

Several factors are taken into account while determining the minimum support price for cotton, such as the economic condition of farmers, market competition, costs of production, and various other relevant elements. By judiciously analyzing all these factors the government determines the appropriate minimum support price for the farmers.

The minimum support price for cotton is determined under the Green Revolution Scheme. It attempts to protect farmers from price market irregularities and natural disasters. Further, the Minimum Support Price is revised by the Government from time to time to accommodate possible variations in production.

The minimum support price for cotton is determined per quintal (100 kg). This value varies depending on the region and financial year. Agreements are made between the State Governments and the Central Government to establish the Minimum Support Price.

Farmers have the right to sell cotton at the minimum support price, but according to the market condition they can also sell their products at the market price. Apart from this, farmers are guaranteed to purchase their products at the minimum support price set by the government. It provides proper incentives to farmers for production and ensures them economic security.

Download Our App "SIS CONNECT" For Daily Updates. CLICK HERE

FOR MORE INFORMATION
CONTACT - +91 - 91119 77775

CAI retains its January cotton pressing estimate for 2023-24 cotton season at 294.10 lakh bales

COTTON ASSOCIATION OF INDIA

INDIAN COTTON BALANCE SHEET FOR THE SEASON 2023-24 AND 2022-23

Estimated as on 31st January 2024

Details	2023-24		2022-23	
	(in lakh b/s)	(in'000 Tons)	(in lakh b/s)	(in'000 Tons)
Supply				
Opening Stock	28.90	491.30	24.00	408.00
Cotton Pressing	294.10	4999.70	318.90	5421.30
Imports	22.00	374.00	12.50	212.50
Total Supply	**345.00**	**5865.00**	**355.40**	**6041.80**
Demand				
Mill Consumption	280.00	4760.00	280.00	4760.00
Consumption by SSI Unit	15.00	255.00	15.00	255.00
Non- Mill Consumption	16.00	272.00	16.00	272.00
Total Domestic Demand	**311.00**	**5287.00**	**311.00**	**5287.00**
Available Surplus	**34.00**	**578.00**	**44.40**	**754.80**
Exports	**14.00**	**238.00**	**15.50**	**263.50**
Closing Stock	**20.00**	**340.00**	**28.90**	**491.30**

The Cotton Association of India (CAI) has retained its January estimate of cotton pressing numbers for the 2023-24 season at 294.10 lakh bales of 170 kg. Total cotton supply by the end of January 2024 is estimated to be 210.05 lakh bales, including arrivals, imports and opening stocks. Cotton consumption by the end of January 2024 is estimated to be 110.00 lakh bales, while export shipment by January 31, 2024 is estimated to be 9.00 lakh bales.

CAI has estimated the stock at the end of January 2024 to be 91.05 lakh bales, which includes 41.00 lakh bales with textile mills and the remaining 50.05 lakh bales with CCI, Maharashtra Federation and others. The total cotton supply by the end of 2023-24 season (by September 30, 2024) is estimated to be 345 lakh bales.

The Crop Committee of CAI in its meeting on February 20, 2024 maintained the cotton consumption estimate for the 2023-24 season at 311 lakh bales. Cotton pressing estimate for the season is 294.10 lakh bales. Cotton import for the season is estimated at 22 lakh bales and export at 14 lakh bales. The ending stock by September 30, 2024 is estimated to be 20 lakh bales.

Cotton arrival this week in major cotton producing states across the country

SMART INFO SERVICES

ALL INDIA COTTON WEEKLY ARRIVAL

CALL : 91119 77775

STATE	19.02.24	20.02.24	21.02.24	22.02.24	23.02.24	24.02.24
PUNJAB	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,000
HARYANA	3,500	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500
UPPER RAJASTHAN	5,000	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000
LOWER RAJASTHAN	3,500	3,500	3,500	2,500	3,000	3,000
NORTH ZONE	13,000	11,500	11,500	11,500	11,700	11,500
GUJRAT	38,000	38,000	38,000	38,000	37,000	33,000
MADHYA PRADESH	8,000	7,500	7,500	7,500	7,500	6,000
MAHARASHTRA	40,000	40,000	40,000	35,000	40,000	40,000
CENTRAL ZONE	86,000	85,500	85,500	80,500	84,500	79,000
KARNATAKA	11,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ANDHRA PRADESH	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
TELANGANA	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
TAMILNADU	800	800	800	300	500	500
SOUTH ZONE	23,800	24,800	24,800	24,300	24,500	24,500
ODISHA	1,700	1,300	1,300	1,000	900	800
TOTAL	124,500	123,100	123,100	117,300	121,600	115,800
ARRIVAL IN 170 Kg.						

Indian textile industry welcomes removal of import duty on ELS cotton

The Indian textile industry has not only welcomed the move to remove import duty on extra-long staple (ELS) cotton but also hopes that the government will soon realize the need to eliminate duty on other cotton varieties. After this decision, cotton prices in Gujarat market fell by Rs 600 per candy of 356 kg due to immediate pressure on market sentiment. However, prices improved .to some extent on Wednesday

The Central Government has removed import duty on ELS cotton. The country is heavily dependent on imports of ELS cotton. At present, around 11 per cent import duty is applicable on raw material used for fine counting of cotton yarn. "This is a worthy step," said managing director of TT Industries and former president of the Confederation of Indian Textile Industry (CITI). We .hope that the import duty on other varieties of cotton will be reviewed sooner or later

The government has to maintain a balance between the competitiveness of the industry and the protection of the farmer through MSP. He said India is a net importer of ELS cotton as the country does not grow enough cotton to meet the requirements. Import duty had made Indian value-added products made from yarn of 60/1 and above expensive. The farmers did not get any benefit. .The government has rectified a mistake

The removal of import duty may provide some relief to the textile value chain of high-end fabrics," said Bharat Shah, a power-" loom owner from Ichalkaranji in Maharashtra. For good quality clothes and garments, the production cost may be slightly reduced. He said that the psychological impact on the market sentiment of cotton may be seen only for a few days. The overall .market dynamics will not change due to the government's decision

A leading cotton yarn trader from Delhi said that the consumption of ELS cotton is very less out of the total cotton requirement. Therefore this decision will have very limited impact. It cannot replace Shankar-6 cotton of Gujarat as ELS cotton is very expensive. Trade sources said cotton prices fell by Rs 600 per candy in the Gujarat market on Tuesday after the news broke. Sentiment .weakened due to wait and see policy of cotton buyers. However, prices increased by ₹200 per candy on Wednesday

TOP 4 NEWS OF THE WEEK

- **Maharashtra: Farmers' agitation in Beed district Chhatrapati Sambhajinagar regarding cotton purchase price.**
  Chhatrapati Sambhajinagar: Two farmers from Beed district demonstrated outside the District Collector office on Friday over low prices of cotton in the market.

- **Center has proposed 5-year guaranteed procurement at MSP for 5 crops – cotton, maize, tur, urad and lentil**
  However, there is no commitment on the law sought by farmers that could force private traders to buy at least at the benchmark rate, if not higher.

- **Telangana urges CCI to continue cotton procurement to prevent fall in prices**
  Telangana Agriculture Minister Tummala Nageswara Rao has urged the Cotton Corporation of India (CCI) to continue purchasing cotton in the state.

- **Telangana: CCI procured 12.31 lakh tonnes of cotton**
  The third picking of cotton is going on in almost all the cotton producing districts of the state and huge stock of first and second picking is still lying with the growers.

The physical cotton market witnessed a bullish atmosphere in the fourth week of February, with an upward trend in cotton prices

This week remained bullish for the physical cotton market. Consistent growth was observed in the North, South, and Central zones for the third consecutive week.

In the North zone, Punjab, Haryana, and Rajasthan witnessed an increase of Rs. 25, Rs. 140, and Rs. 125 per maund (unit of weight for commodities) respectively.

Similarly, in the Central zone, an increase of Rs. 400 and Rs. 200 per maund was recorded in Gujarat and Madhya Pradesh states respectively, while no significant change was observed in Maharashtra

In the South zone market, Odisha and Telangana witnessed an increase of Rs. 400 and Rs. 300 per candy respectively. However, no significant change was observed in Karnataka.

SMART INFO SERVICES
india.smartinfo@gmail.com
Call : 91119 77775

DATE: 24.02.2024

WEEKLY COTTON BALES MARKET

STATE	STAPLE LENGTH	19.02.24		24.02.24		CHANGE
		LOW	HIGH	LOW	HIGH	
NORTH ZONE						
PUNJAB	28.5	5,625	5,675	5,650	5,700	25
HARYANA	27.5/28	5,575	5,575	5,600	5,715	140
UPPER RAJASTHAN	28	5,075	5,725	5,150	5,850	125
CENTRAL ZONE						
GUJARAT	29	57,500	58,000	58,200	58,400	400
MADHYA PRADESH	29	56,800	57,300	57,200	57,500	200
MAHARASHTRA	29+ vid.	57,000	57,800	57,200	57,800	0
SMART INFO SERVICES CALL : 91119 77775						
SOUTH ZONE						
ODISHA	29.5+	58,500	58,600	58,900	59,000	400
KARNATAKA	29 mm	57,500	58,000	57,700	58,000	0
TELANGANA	29.5/30 mm 78-80 RD	57,500	58,000	57,800	58,300	300
NOTE : There may be some changes in the rate depending on the quality.						
Punjab, Haryana and Rajasthan rates in maund the rest in Candy						